P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कृषि औद्योगिक समन्वयन और समन्वित ग्रामीण विकास (जनपद गाजीपुर,उ0 प्र0 के सन्दर्भ में भौगोलिक अध्ययन)

अशोक कुमार चौहान
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
डॉ0 आर0 एम0 एल0 अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद

सुनील कुमार प्रसाद
असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
बापू पी0 जी0 कालेज,
पीपीगंज,गोरखपुर

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रधान जनपद गाजीपुर के सम्बन्ध में है। वस्तुतः यह अध्ययन गाजीपुर में ग्रामीण विकास में कृषि किस प्रकार सहायक हो सकती है? पर आधारित है, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र में ग्रामीण विकास भी कृषि पर आधारित होता है। इसलिये केवल कृषि के जीवन निर्वाहक स्वरूप के आधार पर ग्रामीण विकास की कल्पना करना अधिक तर्कसंगत नहीं है। सघन जनसंख्या वाले जनपद गाजीपुर में भी कृषि भरणपोषण का माध्यम है। इसलिए जब तक कृषि को प्रगतिशील नहीं बनाया जायेगा, तब तक वह सम्पूर्ण ग्रामीण विकास में सहायक नहीं होगीं। इसलिये प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि के साथ वहाँ संभावित उद्योगों के विकसित करने की संभावना पैदा करना ग्रामीण विकास का आधार समझने हेतु महत्वपूर्ण है। कृषि पर आधारित अनेक प्रकार के प्रसंस्करण उद्योग तथा कृषि में मांग प्रधान उद्योगों की स्थापना करके कृषि औद्योगिक समन्वयन विकसित किया जा सकता है। क्योंकि समन्वयन की इस प्रक्रिया से कृषि का स्वरूप व्यापारिक होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होगें। इसलिये प्रस्तुत शोध प्रपत्र में सर्वप्रथम कृषि के विकास स्तर और कृष्येत्तर विकास स्तर की गणना कर के दोनों के योग से समन्वित ग्रामीण विकास स्तर की गणना की गई है। पुनः दोनों के साथ समन्वित ग्रामीण विकास की सम्बन्धता की तुलना करके क्षेत्र में कृषि औद्योगिक संभावना वाले क्षेत्रों को पहचाना गया है।

मुख्य शब्द : समन्वयन, प्रखण्डीय विकास, प्रत्यावर्तन

प्रस्तावना

मानवीय सभ्यता का प्राथमिक आर्थिक कार्य भोजन संग्रह, आखेट, कृषि रहे हैं। समयानुसार मानवीय क्षमता के विकास प्राविधिक विकास के साथ–साथ प्राथमिक कार्यों में रूपान्तरण भी होता रहा है। रूपान्तरण की यह प्रक्रिया कालिक और क्षेत्रीय रही है। संभवतः इन प्राथमिक कार्यों में कृषि ही सर्वाधिक विकसित रही है। इसी का रूपान्तरण सर्वाधिक हुआ है। क्योंकि कृषि पर ही मानव की निर्भरता अधिक रही है। इसलिए कृषि प्रारंभिक प्राकृतिक कृषि, स्थानान्तरणशील कृषि, गहन जीवन निर्वाहक कृषि व्यापारिक कृषि और औद्योगिक कृषि के विभिन्न चरणों में रूपान्तरित होती रही है। रूपान्तरण की यह प्रक्रिया प्रत्येक देश और क्षेत्र में अलग–अलग घटित हुई है। स्वाभाविक रूप में यह जनदबाव का परिणाम रहा है। अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर कृषि प्रधान गंगा बेसिन का एक भाग है। जहाँ जनसंख्या का दबाव समयानुसार बढ़ता गया है। इसलिए कृषि भी वहाँ वर्तमान समय में गहन जीवन निर्वाहक हैं, क्योंकि भरणपोषण की व्यवस्था वर्तमान समय में सर्वाधिक आवश्यक है। अकेले कृषि पर आधारित अर्थतन्त्र जनसंख्या की सर्वांगीण आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए कृषि के साथ–साथ अनुषंगी व्यवसायों का विकास भी आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ही वहाँ कृषि के साथ–साथ अन्य कार्यों उद्योगों के विकास का विश्लेषण करना है। इसलिए यह माना गया है कि क्षेत्रानुसार जहाँ कृषि विकसित है, वहीं अनुषंगी कार्यों का विकास भी संभव है। इसी में कृषि औद्योगिक समन्वयन के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। यह समन्वयन ही समन्वित ग्रामीण विकास का आधार है। इस तरह किसी भी क्षेत्र में कृषि औद्योगिक समन्वयन का निर्धारण करके ग्रामीण विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कृषि पर आधारित अर्थतन्त्र के नियोजन का एक प्रतिमान भी बन सकता है।

कृषि औद्योगिक समन्वयन

कृषि औद्योगिक समन्वयन (Agro Industrial Integration) की संकल्पना किसी भी क्षेत्र के सन्दर्भ में कृषि और उद्योग के कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध से है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आर्थिक विकास की धुरी है। अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उस पर भी जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक है। इसीलिये जब तक कृषि को उद्योग के रूप में विकसित नहीं किया जायेगा, तब तक कृषि जनसंख्या की आवश्यकता पूरी नहीं कर पायेगी। इसलिए प्रचलित कृषि को तकनीकी, नवाचार और पूंजी निवेश से प्रगतिशील करके कृषि उत्पादों पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योगों की संभावना विकसित करनी होगी। तभी कृषि ग्रामीण विकास का आधार बन सकती है। ऐसे बहुत से कृषि उत्पादन हैं। जिनके आधार पर उद्योग विकसित किये जा सकते हैं। जो भी संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, उन पर ही कृषि पर आधारित उद्योग विकसित करने की संभावना खोजनी होगी। क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही अनेक कारक उद्योगों के विकास के लिये उपलब्ध है। जैसे कृषि उत्पादन, विपणन केन्द्र, सस्ता श्रम, विशाल बाजार आदि तत्व पहले से ही स्थापित हैं। केवल ऊर्जा, पूंजी निवेश करके कृषि औद्योगिक भूदृश्य स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया का परिणाम ही कृषि–औद्योगिक समन्वयन है। यह वास्तव में ग्रामीण विकास का एक वैकल्पिक माडल है। जिसमें कृषि पर ही आधारित उद्योग विकसित करके ग्रामीण अर्थतन्त्र को मजबूत किया जा सकता है। कृषि औद्योगिक समन्वयन को एक प्रतिमान के रूप में निम्न लिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है।

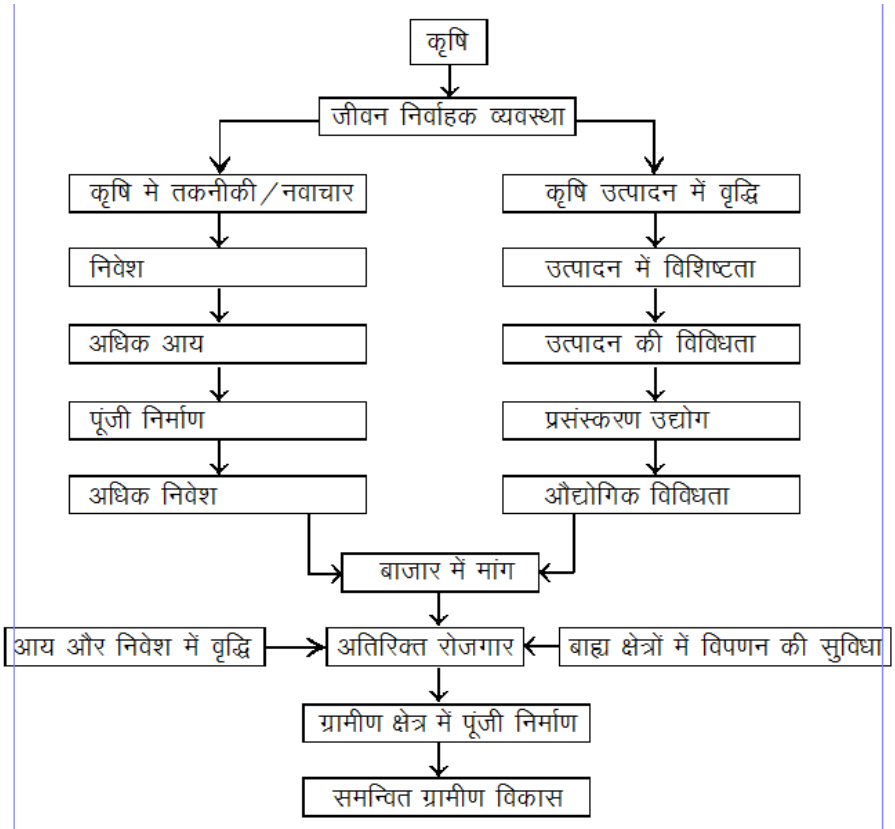

कृषि औद्योगिक समन्वयन

उक्त प्रतिमान से स्पष्ट है कि परम्परागत कृषि से जैसे–2 कृषि प्रगति करती जायेगी–ठीक उसी के साथ कृषि उत्पादन पर आधारित लघु एवं छोटे उद्योग विकसित होगें तो कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक होते जायेंगे तथा कृषि–औद्योगिक समन्वयन विकसित होता जायेगा जो अन्ततः ग्रामीण विकास को ही प्रोत्साहित करेगा। जब इस तरह ग्रामीण विकास प्रतिरूप विकसित होगा तो धीरे–धीरे नीचे से ऊपर की ओर अतिरेक उत्पादन प्रवाहित होगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र नगरीय अर्थतन्त्र का शोषण क्षेत्र न होकर क्रिया प्रतिक्रिया से कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध विकसित हो जायेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण तथा निवेश भी प्रारंभ हो जायेगा। यही ग्रामीण विकास का उन्नत स्वरूप है।

समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना

समन्वित ग्रामीण विकास ग्रामीण परिवेश के गुणात्मक परिवर्तन हेतु नियोजन एवं प्रक्रियाओं कें चयन की एक संकल्पना है, जो ग्रामीणों के कल्याण एवं सामाजिक एकीकरण की एक प्रक्रिया है। जिसे प्राकृतिक आर्थिक, संस्थागत एवं प्राविधिक अन्तर्सम्बन्धों एवं उनके भावी परिवर्तन को संयोजित कर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अत्यधिक उत्पादन, अधिकतम रोजगार एवं आय के अपेक्षाकृत समान वितरण के साथ ही साथ निर्बल वर्ग की उत्पादन प्रक्रिया में अधिकाधिक सहभागिता एवं

न्याय संगत वितरण का प्रयास ही समन्वित ग्रामीण विकास का उद्देश्य है (शर्मा एवं मल्होत्रा 1977)[1]

भूगोल के अन्तर्गत विकास अथवा आर्थिक क्रियाकलाप का क्षेत्रीय अर्न्तसम्बन्ध होता है। अर्थात किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर विभिन्न संरचनात्मक तथ्यों का रूपान्तरण ही ग्रामीण विकास है। संरचनात्मक तथ्यों के अन्तर्गत अर्थतन्त्र के विभिन्न आयाम आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और राजनीतिक तंत्र सम्मिलित होते हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में इन्हीं तथ्यों के समयानुसार और सापेक्षिक रूप में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन को ही समन्वित ग्रामीण विकास माना जा सकता है।

हार्टशोन[2] ने 1959 में विकास की क्षेत्रीय संकल्पना को स्पष्ट करते हुए यह बताया है कि विकास एक निर्पेक्ष शब्द नहीं है बल्कि यह एक सापेक्षिक अर्थ वाला शब्द है। इसके अनुसार विकास की कोई अन्तिम सीमा नहीं होती है। यह किसी क्षेत्र अथवा समुदाय के सन्दर्भ में तुलनात्मक रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

भौगोलिक रूप से किसी ग्रामीण क्षेत्र के सन्दर्भ में आर्थिक विकास प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों एवं मानव समाज की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषताओं, रूढ़ियों एवं परम्पराओं पर निर्भर है। इसलिए क्षेत्रीय विकास को निर्धारित करने वाले अनेक तत्व हैं। जो एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में अलग–अलग भी हो सकते हैं क्योंकि विभिन्न संस्थाओं में अर्न्तक्रिया करके ही सापेक्षिक विकास स्तर को प्राप्त किया जा सकता है एवं अर्न्तक्रिया करने वाली मानवीय क्षमता अथवा तकनीकी विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से मानव समाज का इतिहास, उसकी परम्पराओं का विकास उसकी क्षमता को विकसित करने में अलग–अलग प्रकार से अपना योगदान देते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवेश के रूपान्तरण से सम्बन्धित है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत तत्वों तथा उत्पादन प्रक्रिया और जनसंख्या के मध्य समन्वयन स्थापित करके उनके जीवन स्तर में मात्रात्मक एव गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह समन्वित ग्रामीण विकास विभिन्न तत्वों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हेतु समन्वित ग्रामीण विकास एवं क्रियान्वयन की एक संकल्पना है, जो मनुष्य के संर्वागीण कल्याण से सम्बन्धित है और मानव कल्याण के इस स्तर को प्राकृतिक, आर्थिक, संस्थागत एवं प्राविधिकी अर्न्तसम्बन्धों को उनके भावी रूपान्तरण को संयोजित करके प्राप्त किया जा सकता है (पाण्डये एवं तिवारी 1989)[3]

ग्रामीण विकास वास्तव में सामाजिक–आर्थिक विकास का ही एक अंग है। लेकिन इसमें क्षेत्र विशेष के सन्दर्भ में ग्रामीण भूदृश्य के रूपान्तरण पर बल दिया जाता है । एक सीमा तक इसको समन्वित ग्रामीण विकास का पर्याय माना जा सकता है। यद्यपि ग्रामीण विकास को किसी नगरीय विकास के सन्दर्भ में अलग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि विकास प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में समन्वित रूप में घटित होती है, जिसमें ग्रामीण अथवा नगरीय दोनों संरचनात्मक रूप में होते हैं। इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास में ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक तंत्र रूपान्तरित होता है, (आर्य,1999)[4]

भौगोलिक रूप में ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण संरचना में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। ताकि वहाँ क्रमशः बढती हुई जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो सके। गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय संसाधनों के उपभोग का इस तरह प्रारूप निश्चित किया जाता है। जिसमें संसाधनों के उपयोग का लाभ समाज के न्यूनतम स्तर तक पहुँच सकें और इसके साथ ही स्थानीय जनसंख्या की सहभागिता भी विकास प्रक्रिया में निश्चित हो सकें।

क्षेत्रीय संदर्भ में समग्र विकास की अवधारणा के आधार पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक–सामाजिक प्रतिमानों का विकास किया गया है। विश्व के अनेक देशों में अपेक्षाकृत पिछड़ें अर्थतंत्र और अविकसित क्षेत्रों के संदर्भ में इन प्रतिमानों का प्रयोग व्यवहारिक रूप में किया गया है। भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बहुस्तरीय, बहुपक्षीय, ऊपर से नीचे की ओर प्रसारित होने वाले विकास माडल और प्राथमिकता चयन से संबंधित माडलों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में होता रहा है। अब तक इन माडलों के आधार पर समग्र विकास प्रारूप की जो प्रक्रिया विकसित की गई है, उसके संदर्भ में विकास की प्रवृत्ति केन्द्रीय ही रही है। विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया अभी भी सम्भव नहीं हो पायी है। इसीलिए विकास प्रतिरूप असंतुलित रहा है। यह असंतुलन मनुष्य के क्रियात्मक और सामाजिक क्रिया–कलापों तथा उपलब्ध संसाधनों का परिणाम है। क्रियात्मक व्यवहार बहुत कुछ आर्थिक–सामाजिक और राजनैतिक तथ्यों पर निर्भर करता है। यह सत्य है कि सक्षम एवं सचेत जनसंख्या या क्षेत्र सूचनाओं, तकनीकों एवं नीतियों को अपेक्षाकृत जल्दी ग्रहण कर लेता है जबकि पिछड़े सामाजिक परिवेश वाले क्षेत्रों में सक्रियता का अभाव एवं स्व आरोपित निश्चेष्टा को जन्म देता है। जो विकास प्रक्रिया को बाधित करता है। दूसरी ओर राजनैतिक एवं प्रशासनिक तंत्र विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारम्भिक संसाधन, अवस्थापनात्मक तत्वों का निर्माण तथा संसाधनों के उपयोग पद्धति का निर्धारण तकनीकों का निर्माण एवं उपयोग तथा विभिन्न नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा किये जाते हैं। जो विकास प्रक्रिया को निर्देशित एवं नियंत्रित करते है। तथापि सक्रिय एवं सक्षम जनसंख्या इन सुविधाओं को तेजी से ग्रहण करके विकास प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करती है। इस प्रकार विकास प्रक्रिया एक सतत क्रियाशील प्रक्रिया है, जो मानव के जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। जिसका केन्द्रीय तत्व मानव कल्याण है।

इस तरह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास सम्पूर्ण ग्रामीण भूदृश्य का प्रत्यावर्तन है, जिसमें ग्रामीण विकास के सभी आयाम – आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सम्मिलित रहते हैं। इनका पारस्परिक समन्यवन ही ग्रामीण विकास में समानता और न्यायपूर्ण विशेषताओं को व्यवहार में लाता है। यही समन्वित ग्रामीण विकास है। इस तरह समन्वित ग्रामीण विकास को अधोलिखित रूप में समझा जा सकता है।

1. क्षेत्रीय समन्वयन
2. प्रखण्डीय समन्वयन
3. कालिक समन्वयन
4. सामुदायिक समन्वयन
5. क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समन्वयन

इस तरह अर्थतन्त्र के विभिन्न आयामों के पारस्परिक संयोजन (Integration) के आधार पर ही समन्वित ग्रामीण विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. कृषि औद्योगिक समन्वयन का संकल्पनात्मक विश्लेषण
2. समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना का अध्ययन।
3. समन्वित ग्रामीण विकास के संकेतकों का चयन।
4. समन्वित ग्रामीण विकास स्तर का निर्धारण।

परिकल्पनायें

प्रस्तुत अध्ययन में निम्न परिकल्पनायें प्रस्तावित की गयी हैं।

1. ग्रामीण विकास कृषि विकास पर आधारित होता है।
2. कृषि औद्योगिक समन्वयन कृषि के विकसित स्तर पर ही संभव होता है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण कृषि उत्पादनों से ही प्रारंभ होता है।

आंकड़ा स्रोत एवं विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है। जिसे गाजीपुर जनपद की सांख्यिकी पत्रिका, 2015 से प्राप्त किया गया है।

संकेतक उपागम

किसी क्षेत्र में ग्रामीण विकास के स्तरों के निर्धारण के लिए उपयुक्त संकेतको का चयन आवश्यक हैं। परम्परागत रूप में अर्थशास्त्रियों ने विकास स्तरों का निर्धारण करने के लिए प्रतिव्यक्ति आय अथवा नगरीकरण जैसे–प्रतिनिधि परक संकेतको को लिया है लेकिन ऐसे अकेले संकेतक ग्रामीण विकास की मूल भावना को व्यक्त करने में असमर्थ रहे है।[5] इसीलिए बहुत से अन्य विद्वानों ने ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों के मापन के लिए अधिक संख्या में संकेतको का चयन आवश्यक बताया है।

भारत में इस तरह का प्रथम प्रयास देश के विकास स्तर के मापन में अशोकमित्रा ने सबसे पहले संकेतक उपागम को प्रयोग में लाया– कालान्तर में 8 वें दशक में यादव और प्रसाद[6] ने संकेतक उपागम विधि का प्रयोग विकास स्तरों के निर्धारण में किया। राजस्थान के विकास स्तरों के निर्धारण में शर्मा[7] ने संकेतक विधि का प्रयोग किया। पुनः उड़ीसा के सन्दर्भ में पटनायक और चट्टोपाध्याय[8] ने संकेतको का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में श्री प्रकाश और राजन[9] मिश्रा और गायकबाड़[10] ने मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास के निर्धारण में संकेतको का प्रयोग किया है। रामान्ना और शर्मा[11] ने तेलंगाना क्षेत्र के विकास स्तरों का मापन संकेतक विधि से किया है।

भूगोल में भी संकेतकों का प्रयोग प्रादेशिक वर्गीकरणों में होता रहा है। इनमें फ्रायर[12] गिन्सवर्ग[13] उल्मान[14] आदि ने संकेतक उपागम अपनाया है। गिन्स वर्ग[15] ने विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक प्रखण्डों के मापन में संकेतक उपागम अपनाया है। भूगोल में संकेतक उपागम का प्रयोग सम्बन्धित क्षेत्र और जनसंख्या के सन्दर्भ में दिया गया है, जो आर्थिक विकास के क्षेत्रीय सन्दर्भ के कारण अधिक उपयुक्त है।

इसके साथ ही भूगोलवेत्ताओं ने संकेतको का चयन सम्बन्धित क्षेत्र के संसाधन आधार और उनके उपयोग को निर्धारित करने वाले मानवीय और तकनीकी संकेतकों के चयन को भी उपयुक्त बताया है। प्रायः भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक विकास स्तरों के निर्धारण के लिए संकेतक उपागम को ही अपनाया है। भूगोल के अन्तर्गत संकेतको के चयन को लेकर भी मतभेद रहा है और यह बहस का विषय रहा है कि विकास स्तरों के मापन में किस प्रकार के संकेतकों का चयन उपयुक्त है क्योंकि इनका चयन वस्तु परक अधिक है। उद्देश्य परक नहीं। उनका चयन अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। शाह[16] ने आर्थिक विकास के निर्धारण हेतु विखण्डित संकेतक उपागम का सुझाव दिया है। उनके अनुसार किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास स्तर का मापन एक मात्र संकेतक से नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक विकास के क्षेत्रीय संदर्भ का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। इस तरह संकेतक विखण्डित अथवा संयुक्त हो, वास्तव में आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास के समन्वित प्रतिरूप को विभिन्न प्रखण्डों और आयामों में विभाजित कर लिया जाता है। और प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग–अलग संकेतकों का चयन किया जाता है। पुनः विभिन्न संकेतकों के मूल्यों के आधार पर एक–एक प्रखण्ड के लिए संयुक्त संकेतक प्राप्त किया जाता है और समन्वित प्रतिरूप स्तर ज्ञात करने के लिए प्रखण्डीय मूल्यों को पुनः एक में जोड़ देते हैं। इस तरह किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण विकास स्तर अथवा आर्थिक विकास स्तर का मापन किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में संकेतकों का चयन

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, जहाँ अर्थतन्त्र प्रधानतया कृषि और अनुषंगी कार्यो पर आधारित हैं। इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास के निर्धारण हेतु कृषि सम्बन्धी विशेषताओं को आधार के रूप मे अपनाना महत्वपूर्ण है। क्यों कि कृषि की परिवर्तनशील दशाओं के अनुसार ही ग्रामीण विकास प्रभावित होता है। कृषि अर्थतन्त्र में कृषि विकास के विभिन्न तत्वों के साथ–साथ कृषि विकास के बहुत से अवस्थापना तत्वों की मुख्य भूमिका है। और इस तरह ग्रामीण जनजीवन कृषि से ही प्रभावित है। जबकि समन्वित ग्रामीण विकास में आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त सामाजिक, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि तत्वों की संरचनात्मक विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। सब मिलकर ग्रामीण अर्थ तन्त्र का क्षेत्रीय प्रतिरूप विकसित करते हैं। इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास के संकेतकों के चयन में स्पष्टतया दो प्रारूप दिखायी देते हैं। इनमें से एक कृषि विकास से सम्बन्धित संकेतक और दूसरा कृष्येत्तर विकास से सम्बन्धित संकेतकों को आधार के रूप में लिया जा सकता है। इसी सन्दर्भ में अध्ययन क्षेत्र के समन्वित ग्रामीण विकास को दो प्रखण्डों में बाँटा गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

1. कृषि विकास का प्रखण्ड,
2. कृष्येत्तर विकास का प्रखण्ड। कृष्येत्तर विकास के अन्तर्गत कृषि के अनुषंगी संकेतको शिक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न संकेतको को लिया गया है। वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में बिखरे हुए लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र के ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका सार्थक तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए कृष्येत्तर विकास में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भी संकेतक के रूप में चयनित किया गया है। इस तरह समान्य रूप में दोनों प्रखण्डों के अन्तर्गत संकेतको का चयन निम्न प्रकार से किया गया है–

1. समन्वित ग्रामीण विकास प्रतिरूप को निधारित करने के लिए सर्वप्रथम क्षेत्रीय अर्थतन्त्र को कृषि विकास और कृष्येत्तर विकास में विभाजित किया गया है।
2. दोनों प्रखण्डों में संकेतको का चयन करके उनके निरपेक्ष मूल्य को विकासखण्ड के आधार पर रखा गया है। पुनः विकास खण्ड के अनुसार संकेतको को सापेक्षिक मूल्य प्रदान किया गया है। जो प्रतिशत अथवा जनसंख्या या क्षेत्र से विभाजित कर के प्राप्त किया गया है।
3. इसके बाद विकास खण्ड के अनुसार संकेतको का मूल्य निम्नलिखित सूत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है।

$$z \text{ स्कोर} = \frac{X - \bar{X}}{\sigma}$$

X = विकासखण्ड वार संकेतकों का निरपेक्ष मूल्य
$\bar{X}$ = संकेतकों का औसत
σ = प्रमाणिक विचलन

उपरोक्त सूत्र द्वारा विकास खण्ड के अनुसार प्राप्त मानक मूल्य औसत से धनात्मक अथवा ऋणात्मक मूल्यों को व्यक्त करते हैं। विकासखण्डवार औसत से अधिक धनात्मक मूल्यों को उनके प्रसार के अनुसार अधिक महत्व और क्रमशः घटते हुए मूल्यों को कम महत्व दिया जाता है। इस तरह ऋणात्मक मूल्यों में घटते हुए क्रम में अधिकतम ऋणात्मक मूल्य को सबसे कम विकसित के रूप में परिभाषित किया जाता है

4. अन्त में विकास खण्ड के अनुसार सभी संकेतको के मूल्यों को आपस में जोड़कर कुल मूल्य प्राप्त करते हैं। जो औसत से धनात्मक रूप में अधिकतम और ऋणात्मक रूप में न्यूनतम विकास को प्रदर्शित करते हैं।

कृषि विकास के संकेतक

इसके अन्तर्गत कुल 10 संकेतक विकास खण्डवार चुने गये हैं।

1. शुद्ध कृषित भूमि का कुल क्षेत्र से प्रतिशत
2. शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
3. मुख्य कर्मकारों में कृषकों का प्रतिशत
4. कुल फसलगत क्षेत्र से खाद्यान क्षेत्र का प्रतिशत
5. प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत किग्रा0 में
6. शस्य गहनता प्रतिशत में
7. कुल ट्रैक्टरों की संख्या कुल योग से प्रतिशत में
8. कुल फसलगत क्षेत्र में व्यापारिक फसलों का क्षेत्र प्रतिशत में
9. उर्वरक बीज विपणन केन्द्रों की संख्या
10. कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या

कृष्येत्तर विकास के संकेतक

1. विकासखण्डवार कुल पजीकृत उद्योगों की संख्या
2. लघु उद्योगों की संख्या
3. खादी ग्रामोद्योगों की संख्या
4. प्रति दस हजार जनसंख्या पर उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
5. साक्षरता प्रतिशत में
6. परिवारिक उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों का मुख्य कर्मकरो से प्रतिशत
7. कुल आबाद ग्रामों में विद्युती कृत ग्रामों का प्रतिशत
8. प्रति 100 आबाद ग्रामों में बायोगैस संयन्त्रों की संख्या
9. प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई
10. प्रतिलाख जनसंख्या पर अस्पतालों की संख्या
11. प्रतिलाख जनसंख्या पर उपलब्ध शैयाओं की संख्या
12. स्वास्थ्य सुविधा से युक्त आबाद ग्रामों का प्रतिशत
13. पक्की सड़कों से जुड़े आबाद ग्रामों का प्रतिशत
14. प्रति व्यवसायिक बैंक सेवित कुल जनसंख्या

संकेतको के उपरोक्त विकासखण्डवार मूल्यों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न संकेतको के वितरण प्रतिरूप में औसत से अधिक अथवा कम मूल्यों में समानता अधिक है। अर्थात 0 से धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों के अनुसार जो संकेतक धनात्मक मूल्य रखते हैं। वे समान रूप में हर संकेतक में धनात्मक है अथवा ऋणात्मक मूल्य रखने वाले संकेतको में हर विकास खण्ड में समानता पायी जाती है।

मानचित्र 1

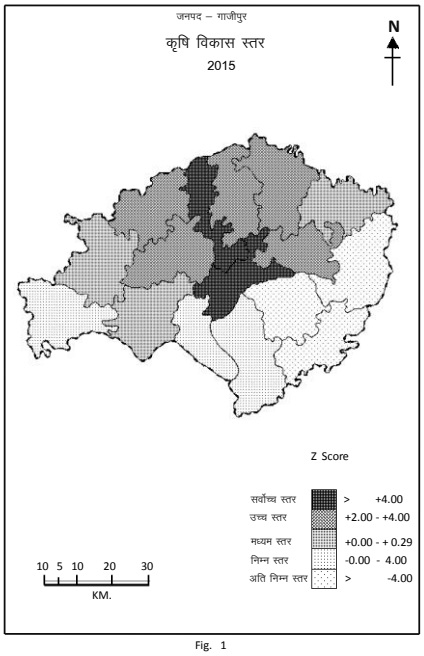

Fig. 1

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका 1

जनपद गाजीपुर में विकास स्तरों के समन्वित जेड मूल्य 2015

क्र.सं.	विकासखण्ड	कृषि विकास स्तर	कृष्येत्तर विकास स्तर	समन्वित ग्रामीण विकास स्तर
1	जखनिया	+ 3.37	− 2.51	+ 0.86
2	मनिहारी	+ 3.65	+ 0.21	+ 3.86
3	सादात	+ 0.54	+ 1.45	+ 1.99
4	सैदपुर	− 1.88	+ 1.63	− 0.25
5	देवकली	+ 1.35	− 6.86	− 5.51
6	विरनो	+ 5.15	+ 2.94	+ 8.09
7	मरदह	+ 3.52	+ 1.95	+ 5.47
8	गाजीपुर	+ 7.39	+ 4.89	+ 12.28
9	करण्डा	− 3.80	− 2.78	− 6.56
10	कासिमाबाद	+ 3.13	− 1.89	+ 1.24
11	बाराचवर	+ 0.96	+ 1.87	+ 2.83
12	मोहम्मदाबाद	+ 2.96	+ 3.92	+ 6.88
13	भावरकोल	− 7.37	+ 0.80	− 6.93
14	जमानिया	− 0.49	+ 3.91	+ 3.42
15	रेवतीपुर	− 8.02	− 5.12	− 13.74
16	भदौरा	− 7.66	− 3.46	− 11.12

कृषि विकास स्तर

इसके अन्तर्गत कृषि विकास के 10 संकेतको के मूल्यों को जोड़कर समन्वित संकेतक प्राप्त किया गया है, जो कृषि विकास स्तर को व्यक्त करता है। तालिका 2 और मानचित्र 1 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषि विकास को प्रति बिम्बित करने वाले संकेतको का मूल्य औसत से अधिक +7.39 गाजीपुर विकास खण्ड और औसत से अधिकतम ऋणात्मक मूल्य −8.02 रेवतीपुर विकासखण्ड का है। इस तरह इन्हीं के बीच में समन्वित मूल्यों का प्रसार है। इन मूल्यों के आधार पर कृषि विकास स्तर को पांच भागों में बाटा गया है। तालिका से स्पष्ट है कि +4 से अधिक मूल्य गाजीपुर और विरनों विकासखण्ड का है, जो कृषि विकास के सर्वोच्च स्तर पर हैं। दूसरा उच्च विकसित स्तर में मूल्य +2 से +4 के बीच मे है। जो जखनिया, मनिहारी, मरदह, कासिमाबाद और मुहम्मदाबाद में मिलता है। मानचित्र के अनुसार इन विकास खण्डो का वितरण अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी और मध्यवर्ती भागों में है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ समतल मैदान, उपजाऊ दोमट मिट्टी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, परिवहन और विपणन केन्द्रों की अधिकता है।

तालिका संख्या − 2

जनपद गाजीपुर में कृषि विकास स्तर 2015

वितरण मूल्य	विकास खण्ड का नाम	श्रेणी
> + 4.00	विरनो, गाजीपुर	सर्वोच्च
+ 2.00 − 4.00	जखनिया, मनिहारी, मरदह, कासिमाबाद, मोहम्मदाबाद	उच्च
+ 0.00 − 2.00	सादात, देवकली, बाराचवर	मध्यम
− 0.00 − 4.00	करण्डा, सैदपुर, जमानिया	निम्न
< − 4.00	भावरकोल, रेवतीपुर, भदौरा	अति निम्न

इसी तरह मध्यम स्तरीय विकास के मूल्य 0 से +2 तक है। इसके अन्तर्गत सादात, देवकली और वाराचवर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न कारणो से मिट्टी उर्वर नही है, सिंचाई के लिए केवल नलकूप उपलब्ध हैं। इसीलिए कृषि अधिक विकसित नहीं है। कृषि विकास का निम्न स्तर 0 से .−4 तक स्कोर वाला है। इसके अन्तर्गत सैदपुर, जमानिया, करण्डा विकास खण्ड सम्मिलित हैं। ये विकास खण्ड गोमती और गंगा नदियों के बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है। जहां असमतल धरातल, बलुअर, दोमट और बलुई मिट्टी की प्रधानता है। इसीलिए कृषि अधिक विकसित नही है। अति निम्न कृषि विकास स्तर −4 मूल्य भावरकोल, रेवतीपुर और भदौरा विकास खण्ड में है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये सभी विकास खण्ड कर्मनाशा नदी के बाढ़ से प्रभावित रहते है और मिट्टी भी रेतीली है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सामान्यतया कृषि विकास उत्तरी–पूर्वी भाग में अधिक हुआ है। जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में कृषि विकास निम्नस्तरीय है। जिसका मुख्या कारण इन क्षेत्रों का नदियों के बाढ़ से प्रभावित होना है। चित्र–1

कृष्येत्तर विकास

अध्ययन क्षेत्र में कृष्येत्तर विकास के अन्तर्गत कृषि के विपरीत उद्योगों, पशुपालन, सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि को लिया गया है। इसके लिए विभिन्न प्रखण्डों से 14 संकेतको का चयन किया गया है। सामान्य रूप में विभिन्न संकेतको के मूल्यों को जोड़कर कृष्येत्तर विकास का संयुक्त संकेतक प्राप्त किया गया है। इसमें मूल्यों का विस्तार औसत अथवा 0 से धनात्मक +4.89, ऋणात्मक की ओर से 0 से .−6.86 तक है। सूत्र के अनुसार इसमें भी 0 से धनात्मक मूल्य अपेक्षाकृत अधिक विकास को, 0 से ऋणात्मक मूल्य कम विकास को व्यक्त करते हैं। इस तरह तालिका संख्या 3 और मानचित्र 2 से स्पष्ट होता है कि कृष्येत्तर विकास प्रतिरूप सामान्य रूप से मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग में अधिकतम और दक्षिणी −

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पूर्वी भाग में न्यूनतम स्तर का विकास है। तालिका से स्पष्ट होता है कि +4 से अधिक मूल्य केवल गाजीपुर विकासखण्ड का है, जो कृष्येत्तर विकास का सर्वोच्च स्तर है। इसी में गाजीपुर नगर और रेल सड़क मार्ग की सुविधा तथा वाराणसी से सीधे सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध हैं। इसलिए कृषि के अतिरिक्त यहाँ कृष्येत्तर कार्य, उद्योगधन्धे, शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य केन्द्र और आर्थिक प्रखण्ड के अन्य तत्वों का केन्द्रीकरण मिलता है। उच्च स्तर के अन्तर्ग +2 से +4 मूल्य वाले विकासखण्ड सम्मिलित हैं। इसमें विरनो, मुहम्मदाबाद तथा जमानिया विकासखण्ड आते हैं। यहाँ उच्च स्तर का कृष्येत्तर विकास मिलता है। विरनो, अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में है। इसका मुख्यालय मऊ गाजीपुर राजमार्ग पर है। जिसमें कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधायें विकसित हुयी हैं। इसी तरह गाजीपुर के पूर्व स्थित मुहम्मदाबाद एक पुराना नगर हैं, जहाँ औद्योगिक और व्यवसायी गतिविधियां पहले से ही विकसित रही हैं, जबकि गाजीपुर के दक्षिण स्थित जमानिया विकासखण्ड आर्थिक दृष्टि से पहले से विकसित रहा है और जमानियां मुख्यालय पटना वाराणसी मुख्य रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण औद्योगिक और शिक्षा सम्बन्धित गतिविधियों का केन्द्र रहा है। इसके लिए इस क्षेत्र में भी कृष्येत्तर विकास उच्च स्तर का पाया जाता है।

मानचित्र 2

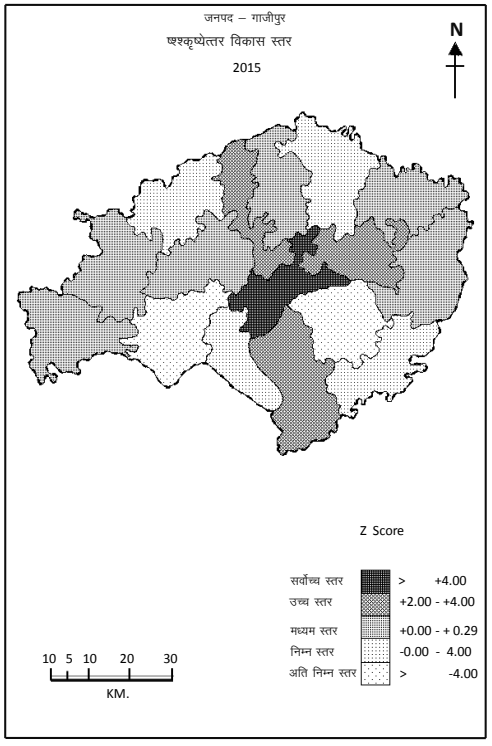

Fig. 2

तालिका संख्या – 3

जनपद गाजीपुर में कृष्येत्तर विकास स्तर 2015

वितरण मूल्य	विकास खण्ड का नाम	श्रेणी
> + 4.00	गाजीपुर	सर्वोच्च
+ 2.00 – 4.00	जमानिया,मोहम्मदाबाद, विरनो	उच्च
+ 0.00 – 2.00	मनिहारी, सादात, सैदपुर, मरदह,बाराचवर,भावरकोल	मध्यम
– 0.00 – 4.00	भदौरा, कासिमाबाद, करण्डा, जखनिया	निम्न
< – 4.00	देवकली, रेवतीपुर	अति निम्न

इस तरह से कृष्येत्तर विकास का मध्यम स्तर 0 से +2 तक मूल्य वाला है। इसके अन्तर्गत सैदपुर सादात, मनिहारी, मरदह, वाराचवर और भावरकोल विकासखण्ड सम्मिलित हैं। इनमे क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम और मध्यवर्ती–पूर्वी भाग में हैं। सैदपुर और सादात वाराणसी गोरखपुर मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, जबकि मरदह, मऊ, गाजीपुरी सड़क मार्ग पर स्थित है। वाराचवर और भावर कोल बलिया के निकट है। इन नगरो के सम्पर्क में रहने के कारण यहाँ कृष्येत्तर विकास मध्यम स्तरीय है। जबकि निम्नस्तरीय कृष्येत्तर विकास का मूल्य 0 से –4 तक है। इसके अन्तर्गत पश्चिमी क्षेत्र का जखनिया, उत्तरी–पूर्वी भाग में कासिमाबाद, दक्षिण में गंगा तट पर करण्डा, दक्षिण–पूर्व में कर्मनाशा तट पर भदौरा विकास खण्ड हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां कृषि विकास भी निम्न स्तर का है। कृष्येत्तर विकास भी निम्न स्तर का है। कृष्येत्तर विकास का अतिनिम्न स्तर –4 से अधिक मूल्य वाला है। इसके अन्तर्गत दक्षिण में देवकली और दक्षिण–पूर्व में रेवतीपुर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। नदी तटवर्ती खादर क्षेत्र और कृषि कार्यों में पिछड़ा होना कष्येत्तर विकास के लिए भी सहायक नहीं है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि अत्यधिक कृष्येत्तर विकास मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में है। जहाँ रेल और सड़क मार्ग की सुविधा है और पहले से ही नगर क्षेत्र विकसित हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास स्तर

प्रस्तुत अध्ययन के लिए समन्वित ग्रामीण विकास स्तर का निर्धारण कृषि विकास स्तर और कृष्येत्तर विकास स्तर को जोड़कर समन्वित मूल्यों के आधार पर किया गया है। विकासखण्ड के अनुसार समन्वित धनात्मक और ऋणात्मक मूल्यों के आधार पर सर्वोच्च स्तर से लेकर न्यूनतम स्तर तक क्षेत्रीय प्रतिरूप ज्ञात किया गया है। तालिका संख्या 1 के अनुसार विकासखण्ड के आधार पर धनात्मक मूल्यों का प्रसार +0.86 से लेकर +12.28 तक है। और ऋणात्मक मूल्यों का प्रसार –0.25 से लेकर – 13.14 तक है। इस तरह स्पष्ट होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता अधिक है। तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास के सर्वोच्च स्तर के अन्तर्ग +6 से अधिक मूल्य वाले विकास खण्ड हैं। जिसमें विरनो, गाजीपुर, मुहम्मदाबाद सम्मिलित हैं। यहां सर्वोच्च ग्रामीण विकास स्तर मिलता है क्योंकि गाजीपुर, मुहम्मदाबाद दोनों महत्वपूर्ण नगर हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

इनके आप–पास परम्परागत कृषि परिवर्तित हो चुकी है। कृषि में सब्जियों की कृषि अधिक की जाती है, जिससे किसानों को नगद मूल्य प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ कृषि विकास अधिक हुआ है। कृष्येत्तर कार्यों का भी यहां अधिक विकास हुआ है, जो सड़क और रेलमार्ग की सुविधा के कारण है। इसी तरह उत्तरी भाग में स्थित मरदह भी सर्वोच्च स्तर वाला है क्योंकि यह क्षेत्र सिंचाई की सुविधा के कारण खाद्यान्नों के साथ–साथ सब्जियों की कृषि में महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप में कृष्येत्तर विकास भी सड़क मार्ग के कारण अधिक हुआ है। इसीलिए ग्रामीण विकास भी अधिक है। समन्वित ग्रामीण विकास का उच्च स्तर +3 से +6 तक के मूल्यों वाला है। इसके अन्तर्गत मनिहारी, मरदह और जमानिया आते हैं। जमानिया में कृष्येत्तर विकास, मनिहारी और मरदह में कृषि विकास अधिक हुआ है। इसलिए ग्रामीण विकास इन क्षेत्रों में उच्च स्तर का है।

मानचित्र 3

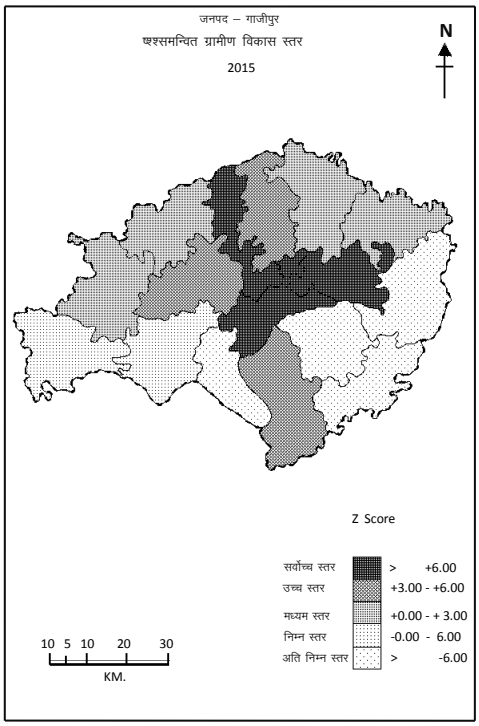

Fig. 3

तालिका संख्या – 4
जनपद गाजीपुर में समन्वित ग्रामीण विकास स्तर 2015

वितरण मूल्य	विकास खण्ड का नाम	श्रेणी
> + 6.00	विरनो, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद	सर्वोच्च
+ 3.00 – 6.00	मनिहारी, मरदह, जमानिया	उच्च
+ 0.00 – 3.00	सादात,कासिमाबाद,बाराचवर, जखनिया	मध्यम
– 0.00 – 6.00	सैदपुर, देवकली	निम्न
< – 6.00	करण्डा, भावरकोल, रेवतीपुर, भदौरा	अतिनिम्न

समन्वित ग्रामीण विकास का मध्यम स्तर 0 से +.32 मूल्य वाला है। जिसके अन्तर्गत पश्चिम में जखनिया और सादात, उत्तर–पूर्व में कासिमाबाद और बाराचवर विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यहाँ मध्यमस्तरीय ग्रामीण विकास का कारण पश्चिमी भाग में मऊ वाराणसी रेलमार्ग की सुविधा और उत्तरी–पूर्वी भाग में बलिया नगर की निकटता है। यहां कृषि विकास और कृष्येत्तर विकास दोनों मध्यम स्तरीय हैं। निम्न स्तर के अन्तर्गत 0 से –6 तक के मूल्य सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत दक्षिण–पश्चिम में दो विकास खण्ड सैदपुर और देवकली हैं। दोनों गोमती और गंगा के तट पर हैं। सामान्य रूप में यहां कृषि और कृष्येत्तर विकास दोनों निम्न स्तर के हैं। केवल सैदपुर में कृष्येत्तर विकास अधिक है जबकि देवकली में कृषि विकास अधिक है। अतिनिम्न स्तर के अन्तर्गत –6 से अधिक मूल्य वाले विकास खण्ड हैं। जो करण्डा, भदौरा, रेवतीपुर और भावरकोल हैं, नदी के कछार से प्रभावित ये विकास खण्ड कृषि अथवा कृष्येत्तर क्षेत्र में भी अतिनिम्न स्तर के हैं। इस तरह स्पष्ट होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास क्षेत्र के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में अधिक हुआ है। जबकि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है।

इस तरह से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद का ग्रामीण विकास मुख्यतया कृषि पर ही निर्भर है क्योंकि ग्रामीण विकास के अन्य प्रखण्ड अभी भी विकसित नहीं हैं। उसमें भी जिन क्षेत्रों में कृषि विकास अधिक है। उन्हीं क्षेत्रों में कृष्येत्तर प्रखण्ड अधिक विकसित है। यह तथ्य सही है कि किसी भी क्षेत्र में अपेक्षाकृत किसी भी प्रखण्ड के अधिक विकसित होने पर अर्थतन्त्र के अन्य प्रखण्ड भी वहां तेजी से आकर्षित होते हैं और उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति अधिक धनात्मक हो जाती है। यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र में गाजीपुर जिला मुख्यालय से उत्तरपूर्व में मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, उत्तर में मरदह, विरनो, मनिहारी और जखनियां कृषि और कृष्येत्तर विकास दोनों में अग्रणी हैं। यहाँ वाराणसी मऊ रेल मार्ग वाराणसी–गाजीपुर–बलिया रेलमार्ग के कई नोडल केन्द्र विपणन केन्द्रों के रूप में विकसित हो गये हैं। मुख्य सड़क मार्गों के कारण सेवा केन्द्र भी विकसित हैं। जिससे यहां अर्थतन्त्र के कई आयाम विकसित हो रहे हैं। इसके ठीक विपरीत कर्मनाशा, गंगा दोआब और दक्षिण पश्चिम में अर्थतन्त्र का कोई भी आयाम अपेक्षाकृत औसत विकास स्तर से भी कम विकसित है। विशेष रूप में विरल जनसंख्या, सड़क मार्ग जाल का विकसित न होना, नोडल केन्द्रों का अभाव आदि कारणों से समन्वित ग्रामीण विकास का निम्न स्तर मिलता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन–जिन क्षेत्रों में कृषि विकास अधिक हुआ है, उन्हीं क्षेत्रों में ग्रामीण विकास भी उच्च स्तर का है। इसलिए यह परिकल्पना पुष्ट होती है कि कृषि विकास का क्षेत्रीय प्रतिरूप और ग्रामीण विकास एक दूसरे से सम्बन्धित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sharma, S.K. and Malhotra, S.L. (1977): Integrated Rural Development: Approaches

Strategy and Perspectives, Abhinav Pub. New Delhi, 30.
2. Hartshorne, R (1960) : Perspective on the Nature of Geography, P.136
3. Pandey, J.N. & Tiwari Rekha (1989) : Integrated Area Development in Proceeding of National Symosium on Spatial Inequality in Regional Development Allahabad.
4. आर्य राजेश कुमार (1999):'मालवा पठार (मध्य प्रदेश) में कृषि आधारित उद्योग एवं ग्रामीण विकास, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध दी0 द0 उ0 गोरखपुर वि0वि0 गोरखपुर, पृ0सं0–7–9
5. Pathak C.R. and Kundu A. (1973) : A Critique of Techniques for Measuring the Levels of Development, a paper presented in a Symposium on Region Disparities, New Delhi
6. Pal, M.N. (1975) : Regional Disparities in the levels of Development in India - Indian Journal of Regional Science. Vol. VII No. 1, PP. 35-52
7. Sharma, K.L. (1975) : Spatial Disparities in Rajsthan : A Comparative Study of Development between two Points of Time. Indian Journal of Regional Science Vol-VII No. 1, PP-90-100
8. Patnayak, S. and Chattopadhyay : Spatial Variation in the Levels of Development in Orissa, Indian Journal of Regional Science Vol VII, No. 1, PP 90-100.
9. Sri Prakash and Rajan, P. (1979) : Regional Inequality of Rural Development in Madhya Pradesh - Indian Journal of Regional Seicne Vol XI, No. 1, PP 1-14
10. Misra, S. K. and Gaikwad S.B. (1979) : Impact of Economic Development on the Welfare and Living Conditions of the People of Madhya Pradesh - Indian Journal of Regional Seicne Vol XI, No. 1, PP 25-33.
11. Ramana, K.V. and Sharma P.V. (1979) : Disparities in Development : A Block Level Study of Telangana Region - Indian Journal of Regional Seicne Vol XI, No. 1, PP 55-57.
12. Frayer D.W. (1958) : World Income and Types of Economy: The Pattern of World Economic Development Economic Geography, 34 (V) 283-303.
13. Ginsburg, N. (1957) : Natural Resources and Economic Development - Annals of the Association of American Geographers 47 (3) 197-212.
14. Ullman, E.L. (1960) : Geographic Theories and under Developed Areas in Ginsburg's (ed) Esays on Geography and Economic Development, - University of Chicago Dept. of Geography Paper 62, P.5
15. Ginsburg, N. (1961) : Atlas of the Economic Development of the World - University of Chicago Press.
16. Shah, N. (1982) : Levels of Economic Development in the Districts of Maharashtra, Approach to the Problems and Key Statistics C.M.I.E., Bombay